आकाशवाणी केन्द्र शिमला

05.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अब राजनीतिक आधार पर नए संस्थान खोलेगी। वे आज शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत के अनुसार, जनसंख्या और भौगोलिक आधार पर भी नए संस्थान खोलने पर विचार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले पांच साल से जिन विधानसभा हलकों की उपेक्षा की जा रही थी, उन हलकों में उनकी सरकार ने नए संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नए संस्थान खोलने से पहले उनमें सभी सुविधाएं, पद और स्टाफ का प्रबंध करेगी, ताकि जनता की समस्याओं का भी समाधान हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों की हालत अच्छी नहीं है और सरकार अगले आठ माह में इस स्थिति को ठीक करेगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरूआत कर दी गई है। यहां पर डॉक्टरों और पेरामेडिकल स्टाफ के सभी पदों को अभी अस्थाई आधार पर भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर–मरीज रेशो पर सरकार काम कर रही है।

संकल्प

प्रदेश विधानसभा ने राज्य में वर्ष 2023–24 के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से शतप्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक संकल्प पारित किया। यह संकल्प मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में पेश किया था और इस संकल्प पर चर्चा भी हुई। संकल्प के अनुसार जिस प्रकार वर्ष 2024–25 के बजट में केंद्र सरकार ने तीन आपदा प्रभावित राज्यों सिक्किम, आसाम और उत्तराखंड के बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तर्ज पर आपदा से भारी नुकसान हुआ था। इसलिए केंद्र हिमाचल को भी शतप्रतिशत सहायता राशि प्रदान करे।

मोबिलिटी कार्ड

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का आज शिमला से शुभारंभ किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिये भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसने इस सुविधा की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज, पश्चिमी मुंबई की बसों में

यात्रा की जा सकेगी और एचआरटीसी की बसों में भी इस कार्ड से कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्ड 100 रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा और इसके बाद लोग बस काउंटर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसका टॉप–अप रिचार्ज करवा सकेंगे।

घटना

किन्नौर जिला के पूह क्षेत्र के तहत गांधी मोहल्ला सम्पर्क मार्ग पर आज सुबह एक पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक सहित 4 अन्य गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। वाहन में कुल 7 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार पूह गांव की 6 महिलाएं मनरेगा कार्य के दौरान पिकअप वाहन में बजरी लेकर गांधी मोहल्ला सड़क से जा रहे थे और अचानक सामुदायिक अस्पताल के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। मृतकों में छेवांग जामो, इन्द्र मोनी और सरिता शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने गम्भीर घायलों को कड़छम स्थित भारतीय सेना के हैलीपैड से एयर लिफ्ट करवा कर उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया है। जगत सिंह नेगी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले 3 परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। पूह के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विनय मोदी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 25–25 हजार जबकि घायलों को 5–5 हजार रूपए की तुरंत राहत राशि प्रदान की गई है।

प्रदर्शन

राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला विधानसभा से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। इस मामले को लेकर विभिन्न हिन्दू संगठनों ने आज संजौली व चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और बाहरी लोग बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हिमाचल आकर आपसी भाईचारे को खराब कर रहे हैं। चौड़ा मैदान में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदर्शन में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह शामिल हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी और मुख्यमंत्री ने इस मामले में कानून के तहत कार्यवाही की बात कही है। विभिन्न हिन्दू संगठनों ने अवैध मस्जिद को हटाने और वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की मांग की।

————————————